

हिमाचल में अब रटकर नहीं समझकर देंगे परीक्षा

धर्मशाला, 10 अक्टूबर (ब्यूरो): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शिक्षा प्रणाली को अधिक विद्यार्थी केंद्रित, कौशल आधारित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

ये नए प्रश्न पत्र परख के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर विद्यार्थियों की विषयगत समझ, तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या-समाधान कौशल का आकलन करना है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इन सुधारों से विद्यार्थियों पर अनावश्यक परीक्षा दबाव कम होगा और वे भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के लिए तैयार हो सकेंगे। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से शिक्षा में हो रहे इन सकारात्मक परिवर्तनों को अपनाने की अपील की है।

रटकर नहीं, समझकर परीक्षा देंगे छात्र

दिव्य हिमाचल ब्यूरो— धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी अब रटकर नहीं, समझकर परीक्षा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित मॉडल प्रश्न-पत्र जारी कर दिए हैं। ये प्रश्न-पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बोर्ड का कहना है कि प्रदेश की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित, कौशल-आधारित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में यह

महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड के अनुसार, नए मॉडल प्रश्न-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और परख टेक्सोनामी के अनुरूप तैयार करवाए गए हैं। इनका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम आधारित जानकारी या रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विषयगत समझ, ज्ञान के अनुप्रयोग, तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या-समाधान की क्षमता का बेहतर आकलन करना है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला, गुणवत्तापूर्ण और

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी प्रतिभा एवं रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है। डा. शर्मा ने बताया कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों पर अनावश्यक परीक्षा-दबाव कम करना, उनमें विषयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा और भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है।

माडल प्रश्नपत्रों में दिखेगा नई शिक्षा नीति का असर : डा. राजेश

जागरण संवाद केंद्र, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी अब रटकर नहीं, बल्कि समझकर परीक्षा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं के लिए संशोधित माडल प्रश्न-पत्र जारी किए हैं। ये प्रश्न-पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के अनुसार, प्रश्नपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और परख वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप तैयार किए हैं। इनमें विद्यार्थियों की विषयगत समझ, ज्ञान के अनुप्रयोग, तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या-समाधान कौशल का आकलन होगा। इससे रटने के बजाय समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा



राजेश शर्मा •
जागरण आर्काइव

व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

शिक्षा का मकसद विद्यार्थियों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने और स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम बनाना है। इसके लिए शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया में लगातार सुधार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि माडल प्रश्न-पत्रों और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव से विद्यार्थियों पर अनावश्यक परीक्षा-दबाव घटेगा, विषयों की समझ विकसित होगी और वे उच्च शिक्षा तथा भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक जरूरतों के लिए तैयार होंगे। डा. शर्मा ने शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और विद्यार्थियों से शिक्षा में हो रहे सकारात्मक बदलाव अपनाने का आग्रह किया।

Impact of NEP-2020 Reflected in Model Question Papers; Revised model question papers released for the 2026-27 academic session



SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA OCT 10 : Students in Himachal Pradesh will now take exams based on understanding rather than rote learning. In alignment with the objectives of the National Education Policy (NEP) 2020, the Himachal Pradesh Board of School Education has released revised model question papers for various examinations scheduled for the 2026-27 academic session. These question papers are available on the Board's official website. The Board states that this is a significant step towards making the state's education and examination system

more student-centric, skill-based, transparent, and quality-oriented. According to the Board, the new model question papers have been prepared in accordance with NEP-2020 and the PARAKH Taxonomy. Their objective is not merely to promote syllabus-based information or rote learning, but to better assess students' conceptual understanding, application of knowledge, logical thinking, analytical abilities, and problem-solving skills. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma stated that NEP-2020 is a crucial initiative aimed at making the Indian education system more inclusive, flexible, high-quality, and aligned with future needs. He remarked that the true purpose of education is not just to prepare students to pass exams, but to empower them to face life's challenges, think independently, and pursue paths suited to their talents and interests. Continuous improvement in teaching and assessment processes is essential for this, and the reforms being made to model question papers and assessment methods are part of this vision. Dr. Sharma explained that the primary goal of these reforms is to reduce unnecessary exam-related pressure on students, foster a deeper understanding of subjects, and prepare them for higher education and future competitive demands. He urged teachers, school management, parents, and students to embrace these positive changes in education and cooperate in achieving the goal of quality education. He stated that the Himachal Pradesh Board of School Education is committed to continuously improving the standard of education in the state and providing students with opportunities aligned with modern requirements.